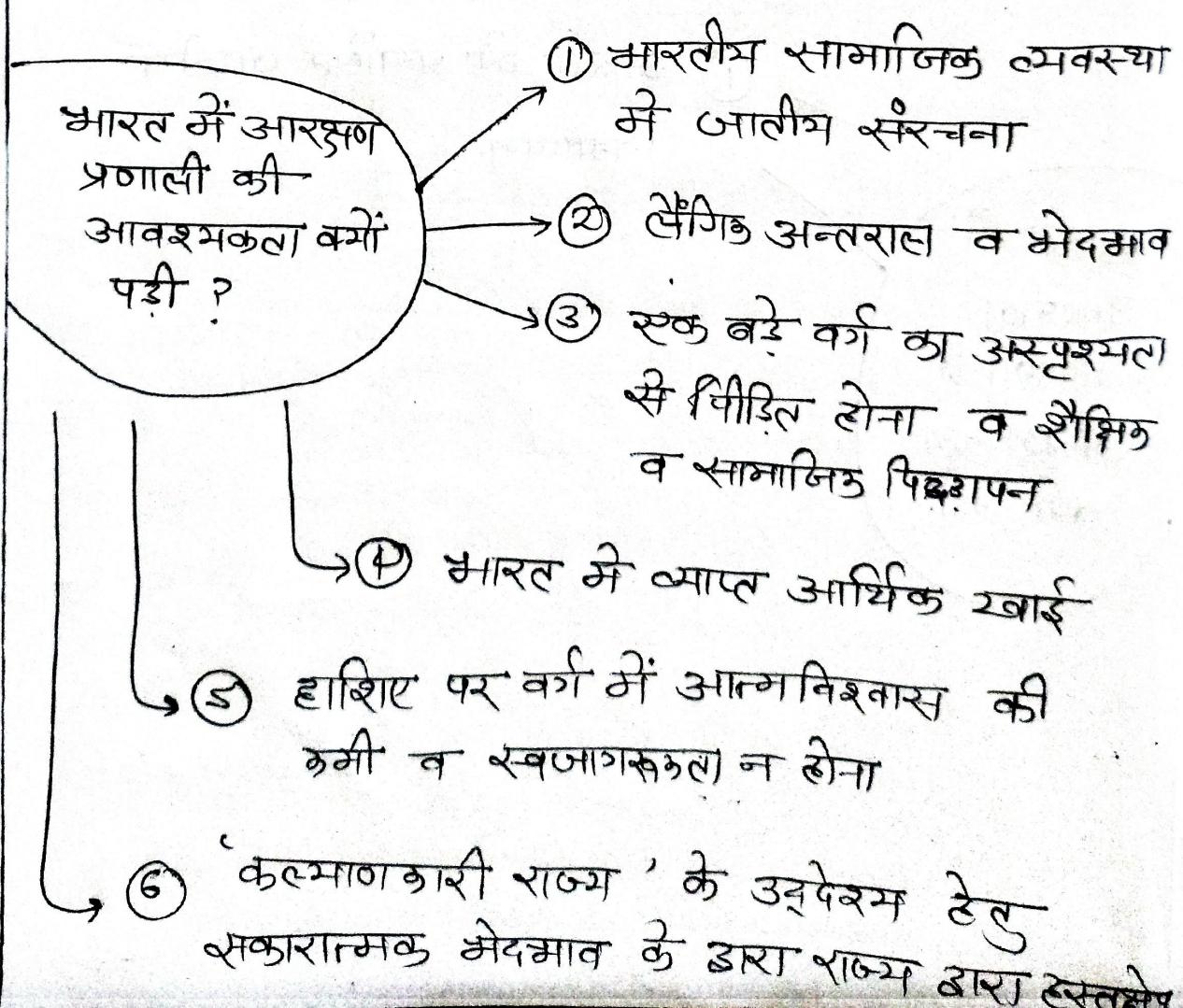


⑥ स्वतंत्रता के ७५ वर्षों के बाद, समाज के संग्रह हित और परिवर्तनकारी संतोषानिकता की आगे बढ़ाने के लिये भारत की आरक्षण प्रणाली पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। सामाजिक व्याप्ति और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिये आरक्षण नीति की पुनः समीक्षा की आवश्यकता का समालिचनात्मक विश्लेषण जीजिट।

आरक्षण एक ऐसा उपकरण है जो वंचितों को समान प्रतिनिधित्व व भागीदारी का अधिकार प्रदान करता है जहाँ वह शिक्षा का द्वीप हो सा शासन का।



भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्षों में आरक्षण प्रणाली
के लिये किसे जरुर प्राप्त

- ① + 1950 में SC, ST के लिये आरक्षण की व्यवस्था
 ↳ 1955 में शाक औलेस्ट्रर के OBC के
 लिये सिफारिश की प्रक्रिया शारिरिक
- ② + 1990 में OBC के लिये अंडेल आपेंग की
 सिफारिश (27% आरक्षण)
- ③ + 2019 में EWS के लिये (सामान्य वर्ग) 10%,
 आरक्षण की व्यवस्था।

आरक्षण प्रणाली की आवश्यकता पर पुनर्विचार की
आवश्यकता क्यों?

पूँ समला के अधिकार विरुद्ध

↳ अवसर की समला की आपेक्षा व प्रवेश पर
आरक्षण की व्यवस्था 'खुली प्रतियोगिता' के
भेदमान सम्बन्धी प्रक्रन छाड़ा भरता है।

(उदाहरण) विहार, झारखण्ड, तमिलनाडु जैसे राज्यों
में 50% से अधिक आरक्षण 'प्रवासनिक वक्ता'
की प्रमाणित भरता है।

② आरक्षण नीति की आड़ में प्रशासित प्रशासनिक
वशीनरी द्वारा ध्वन्यानन्

→ मात्रप्रथा व छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में
जातीय आँखें गें हेर-केर के भारी सम्बन्धी
घोटाले

③ लक्षित कर्म तक सीमित पहुँच

→ आर्थिक कष्ट से सम्पन्न परन्तु पिछले
कर्म से सम्बन्धित लोगों द्वारा आरक्षण वा
अनावश्यक लाभ जो बस्ते उद्देश्यकी शृंति में
आधा भी तरह कार्य कर रहा।

उदाहरण द्वारा भटाराष्ट्र वैन और भेड़ की इजा
भेड़ कर द्वारा उच्च आर्थिक विकास के बावजूद
आरक्षण वा लाभ

④ प्रतिभासम्पन्न युवाओं का ब्रेन ड्रेन

→ आरक्षण प्रणाली से असन्तुष्ट युवाओं
द्वारा विदेशी की तरफ प्रवास

उदाहरण भारत विश्व की प्रेषण प्राप्त कर्ता देशी के
सर्वोत्तम स्थान पर हैं जो बस्ते एक
वडे कर्म के प्रवास की भी दिक्षाल हैं।

इसके अलावा आरक्षण की राजनीतिक
हितों की शृंति हेतु एक दूसरे के काप

→ तमिलनाडु में 10% बिहार में 65% 31/23/2021

सामाजिक व्याप के सामाजिक निकारा सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण नीति की तुला: समीक्षा और आवश्यकता

① आरक्षण नीति की तर्कसंगत बनाने की आवश्यकता

(उदाहरण) क्रीमीलेपर ऐसी अवहारणा व प्रदर्शित की आवश्यकता

② गरीबी मिवारण की जगह सामाजिक उत्थान के दृष्टि के रूप में प्रयोग करने की आवश्यकता

(उदाहरण) कौशल विकास व श्रीजगार सूजन के प्रोत्साहित कर सम्बारणीय पहचान के प्रयोग पर जोक

③ भारिगत व आरक्षण सम्बन्धी उद्योग का डिजीटलीकरण करना

④ आरक्षण पहचान सामाजिक अतिशीलता व समृद्धि की शामिल करना

⑤ आरक्षण की सीमा व सम्पर्कता सुनिश्चित करना व सम्पर्क-सम्पर्क पर समीक्षा सुनिश्चित करना

सीमांचल

① केंद्र व राज्य में आरक्षण
प्रवाली की अवस्था व्यवस्था
उदाहरण बिहार द्वारा आयोजित
जाति आवासित आरक्षण की प्रोत्साहन देगा।

② राज्यों की आरक्षण सम्बन्धी उल्लंघन - उल्लंघन
नीतियों

उदाहरण राज ने कर्नाटक द्वारा OBC की अनुसिद्धि
की भावितव्य दाखिल पर शामिल भरना

सुखाव

① कौशल विकास व रोजगार सूखन की प्रोत्साहन

② गरीबी उन्मुख्य हेतु प्रयास

— अमरेगा, गरीब कल्याण एन्ड प्रोजेक्ट
आदि द्वारा प्रोत्साहन

③ सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर
प्रशिक्षण

④ आरक्षण की सीमांचली की कठोरता के
साथ संग्रह भरना

⑤ जाति व आय सम्बन्धी आड्डों की
पारदर्शिता पर ध्यान

हासिलिंग आरक्षण की नीतियों द्वारा दिये गए परिवर्तन
जो भागिकी के अभावित उत्पान व समावेशी कल्याण
हेतु लापा गया परन्तु अन्योदय से
भवेदित के लक्ष्य की प्राप्त करने हेतु आरक्षण
की वर्तमान की आवश्यकता है।